

# नवचार, उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से 21वीं सदी के शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना: शिक्षा का पुनरुद्धार

श्री सुशील कुमार

रिसर्च स्कॉलर, शिक्षा विभाग, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

## संक्षेप

भारत का साइज़ और वैरायटी, एजुकेशन के नए मॉडल आज़माने के लिए एक आइडियल प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें 21वीं सदी में लीड करने में मदद करेगा। सुधाकर राम कहते हैं, आइए आगे बढ़ने की हिम्मत करें क्योंकि हमारे बच्चों और देश का भविष्य दांव पर लगा है। असल में, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि पढ़ाने के मॉडर्न तरीकों ने जानने की पवित्र जिज्ञासा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन "कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हाल के सालों में दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है, और हैरानी की बात है कि तेज़ी से बदल रही है। फिर भी, हमने पिछले 200 सालों से अपने बच्चों को पढ़ाने का बेसिक तरीका नहीं बदला है। सोचिए कि 60 साल में काम की दुनिया से रिटायर होने से पहले हमारे बच्चों को किन बदलावों का सामना करना पड़ेगा। क्या एजुकेशन को लेकर हमारा अभी का तरीका इन बच्चों को नई दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करने में काफी होगा? एल्विन टॉफ़लर ने 'द थर्ड वेव' में मास एजुकेशन को इंडस्ट्रियल एज के फैक्ट्री मॉडल पर बना बताया है, जिसमें बेसिक पढ़ना, लिखना और मैथ, थोड़ा इतिहास और दूसरे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं – यह एक खुला करिकुलम है। इसके नीचे एक छिपा हुआ करिकुलम था जो कहीं ज़्यादा बेसिक था। इसमें तीन कोर्स थे – पंचुएलिटी, ओबिडियंस और रिपिटिटिव काम – ये भरोसेमंद, प्रोडक्टिव फैक्ट्री वर्कर बनाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरतें हैं। क्या 21वीं सदी की दुनिया को बस इन्हीं काबिलियत की ज़रूरत होगी? अभी का एजुकेशन सिस्टम — स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर — यह मानता है कि 'नॉलेज' सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। ज़ोर इस बात पर है कि इस नॉलेज को जितना हो सके उतने सालों की एजुकेशन में ठूस दिया जाए। एजुकेशन पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या है। लेकिन, इंडिया में चैलेंज इतने बड़े हैं कि यह हमें इनोवेट करने का सबसे बड़ा मौका देता है। हमारा साइज़ और वैरायटी एजुकेशन के कई नए मॉडल आज़माने के लिए एक आइडियल प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें 21वीं सदी में लीड करने में मदद करेंगे।

**कीवर्ड:** इंडस्ट्रियल, प्रोडक्टिव, इनोवेट, आइडियल, एजुकेशन

## 1. इंट्रोडक्शन

भारत में चुनौतियाँ और भी ज़्यादा हैं। स्कूल जाने की उम्र के 200+ मिलियन बच्चों में से, 35% प्राइमरी स्कूल के बाद और 50% अपर प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। ग्रेजुएट होने की उम्र के 20 मिलियन युवाओं में से, सिर्फ़ लगभग तीन मिलियन ही असल में कॉलेज तक पहुँच पाते हैं, और 500,000 से भी कम को नौकरी के लायक माना

जाता है। हमें कई मोर्चों पर शिक्षा के बारे में फिर से सोचने की तुरंत ज़रूरत है। सबसे पहले, हमें प्राइमरी स्कूलों में सीखने के लिए प्यार को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अच्छी तरह से रिसर्च किए गए सिस्टम हैं - जैसे मॉटेसरी मेथड - जो पूरी तरह से बच्चों पर केंद्रित हैं और सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार और असरदार बनाते हैं। पढ़ाने के नए तरीकों में वीडियो-बेस्ड लर्निंग को टीचर के बनाए गेम्स के साथ जोड़ा जा सकता है जो बच्चे के नैचुरल टैलेंट को बढ़ाते हैं। प्राइमरी स्कूलों को बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए — पढ़ना, लिखना, अरिथमेटिक, एनवायरनमेंटल साइंस, हेल्थ और हाइजीन और सोशल/इंटर-पर्सनल स्किल्स। दूसरा, अपर प्राइमरी स्कूलों का फोकस (a) बच्चों को सीखना सिखाना और (b) उनकी नैचुरल काबिलियत को खोजने में उनकी मदद करना होना चाहिए। सीखने के साइंटिफिक तरीके में अच्छी ग्राउंडिंग देना बहुत ज़रूरी है। सीखना सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स जानने से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों को यह दिखाना होगा कि सेल्फ-अवेयर कैसे बनें, और अपनी ज़िंदगी को कैसे देखें: उनकी ज़िंदगी के स्टेज, ज़िंदगी का मकसद। तीसरा, हाई स्कूल के सिलेबस में एग्जाम रिजल्ट्स पर ज़ोर देने के बजाय, कई सबजेक्ट्स में पक्की स्किल्स और काबिलियत बनाने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक टीम एक्सपर्ट गाइडेंस में अपने स्कूलों में सोलर-बेस्ड पावर सिस्टम के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन का काम कर सकती है — प्रोजेक्ट के टेक्निकल, फाइनेंशियल और सोशल पहलुओं पर ध्यान देते हुए। दूसरी टीम अपने लोकल एरिया में बच्चों के साथ गलत व्यवहार को कम करने पर फोकस कर सकती है। इस प्रोसेस में, टीम थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स को समझेंगी और ज़रूरी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करेंगी। चौथा, भविष्य की यूनिवर्सिटीज़ को लाइफ-लॉन्ग लर्निंग मॉड्यूल्स ऑफर करने चाहिए जो लोगों को ज़रूरत के समय ज्ञान हासिल करने में मदद करें। भारत की पेटेंट फाइलिंग सिर्फ एक दशक से ज़्यादा समय में दोगुनी हो गई है, जो 2014 में लगभग 40,000 से बढ़कर 2025 तक 80,000 से ज़्यादा हो गई है। देश अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40वें स्थान पर है, जो 2015 में 81वें स्थान पर था, जो लगातार पॉलिसी फोकस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के असर को दिखाता है। आज भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए जाना जाता है। जब हम स्टार्टअप इंडिया और एजुकेशन सेक्टर के बीच डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन पर बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया और एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। जहाँ 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी सरकारी पॉलिसी ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, वहीं एजुकेशन सेक्टर में एड-टेक स्टार्टअप के आने से लर्निंग बदल रही है। साथ मिलकर, वे इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जॉब्स बना रहे हैं और एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच कोलेबोरेशन के ज़रिए स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए भारत को 'जॉब सीकर इकॉनमी' से जॉब-क्रिएटिंग इकॉनमी में बदल रहे हैं।

### **1.1 डिजिटल एजुकेशन से स्किल डेवलपमेंट तक:**

स्टार्टअप इंडिया एजुकेशन सेक्टर को नई दिशा दे रहा है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप: यह हैकथॉन, इनक्यूबेटर और एकेडमिक पार्टनरशिप के ज़रिए इनोवेशन को बढ़ावा देता है, युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत को मज़बूत करता है। इसके अलावा, जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उदाहरण के लिए, फिनटेक, स्पेसटेक और AI जैसे सेक्टर में, नई जॉब्स पैदा हो रही हैं, जिससे भारत जॉब-क्रिएटिंग देश बन रहा है।

### **1.2 स्टार्टअप इंडिया के बाद एजुकेशन सेक्टर में बदलाव:**

टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन: एडटेक स्टार्टअप्स ने एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, जिससे सीखना आसान और ज़्यादा एंगेजिंग हो गया है, जैसे LMS, मोबाइल लर्निंग, वगैरह। सेल्फ-लर्निंग को बढ़ावा: ऑनलाइन एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को अपनी स्पीड से सीखने और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में मदद की है और इंस्टीट्यूशन को

बदल दिया है। उदाहरण के लिए, कॉलेज इनोवेशन काउंसिल्स (IICs) और इनक्यूबेटर्स के ज़रिए स्टार्टअप हब बन रहे हैं, जो आइडियाज़ को इंडस्ट्री लेवल (TRL लेवल) तक ले जाते हैं।

### **1.3 स्टार्टअप इंडिया तालमेल को बढ़ावा दे रहा है और एक बेहतर भविष्य बना रहा है:**

इंडस्ट्री-एकेडमिक सहयोग: IIT और IIM जैसे संस्थान इंडस्ट्री पर फोकस करने वाली लैब बना रहे हैं, जिससे शिक्षा और मार्केट की मांग के बीच का अंतर कम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्किल इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी पहल युवाओं को नई टेक्नोलॉजी (AI, IoT) में महारत हासिल करने में मदद कर रही हैं ताकि वे स्टार्टअप शुरू कर सकें।

### **1.4 चुनौतियाँ और मौके:**

रेगुलेटरी रुकावटों को दूर करने और एकेडेमिया-इंडस्ट्री सहयोग को गहरा करने से भारत को अपनी एंटरप्रेन्योरियल क्षमता को पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। इस तरह स्टार्टअप इंडिया पहल ने एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच एक मजबूत पुल बनाया है, जिससे भारत एक नॉलेज-बेस्ड इकॉनमी के तौर पर डेवलप हो रहा है।

## **2. स्टडी का मकसद**

**2.1** गांव के अनस्किल्ड लोगों के डेवलपमेंट के लिए NRLM (नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन) के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना।

**2.2** स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की पॉलिसी का पता लगाना।

**2.3** एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए युवाओं को एम्पावर करने में स्किल इंडिया की भूमिका को देखना।

## **3. रिसर्च मेथडोलॉजी**

**3.1** रिसर्च डिज़ाइन मेथडोलॉजी में, मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन मेथड अपनाता हूँ। इस मेथड में सबसे पहले लिटरेचर से डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर संबंधित सब्जेक्ट के लिए जानकार लोगों से जानकारी ली जाती है।

**3.2** डेटा

कलेक्शन मेथड: इस मेथड में प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड दोनों का इस्तेमाल होता है।

## **4. भारत का इनोवेशन रेनेसां, पॉलिसी रिफॉर्म और यूथ एम्पावरमेंट:**

29 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव, इनोवेशन के लिए ग्लोबल हब बनने की भारत की ख्वाहिश की तरफ एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया, यह कॉन्क्लेव सिर्फ एक सेरेमोनियल गैदरिंग नहीं थी, बल्कि एक पॉलिसी-अलाइंड कैटलिस्ट थी जिसने इनोवेशन को बढ़ावा देने, डीप-टेक एडवांसमेंट को आगे बढ़ाने और भारत के युवाओं को एम्पावर करने के लिए सरकार, एकेडेमिया, इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को दिखाया। यह आर्टिकल कॉन्क्लेव में अनाउंस और हाइलाइट किए गए खास पॉलिसी टेकअवे और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव पर डिटेल् में बात करता है।

**4.1** एजुकेशन और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉलिसी का ज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत का डेवलपमेंटल विज़न टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की तिकड़ी पर बहुत ज़ोर देता है—एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसका मकसद देश की बड़ी इंसानी क्षमता का इस्तेमाल करके सस्टेनेबल, इनक्लूसिव ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। इस विज़न

के सेंटर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 है, जो एक बदलाव लाने वाला ब्लूप्रिंट है जो तेज़ी से बदलती ग्लोबल इकॉनमी की मांगों को पूरा करने के लिए भारत के एकेडमिक माहौल को नई दिशा देता है। NEP 2020 मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और शुरुआती क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग को जोड़ने पर ज़ोर देता है, जो रटने की आदत से हटकर ज़्यादा इंकायरी-बेस्ड, लर्नर-सेंट्रिक अप्रोच की ओर इशारा करता है।

इस विज़न को लागू करने के लिए, सरकार ने एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) पेश किया है जो क्लासरूम कंटेंट को 21वीं सदी के लिए ज़रूरी कॉम्पिटेंसी के साथ जोड़ता है। PM ई-विद्या, दीक्षा और स्वयं जैसी पहलों ने लाखों लोगों तक डिजिटल लर्निंग की पहुँच बढ़ाई है, जिससे शहरी-ग्रामीण अंतर कम हुआ है। खास तौर पर, 30 से ज़्यादा भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्टबुक का ट्रांसलेशन कल्चरल और भाषाई इनक्लूसिविटी पक्का करता है, जिससे अलग-अलग इलाकों के स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा या पसंदीदा भाषा में कालिटी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। इनोवेशन के मामले में, भारत रिसर्च और डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चरल बदलाव देख रहा है। रिसर्च पार्क की संख्या 2014 से पहले सिर्फ़ तीन से बढ़कर आज 13 हो गई है, जो ज़रूरी हब के तौर पर काम कर रहे हैं जहाँ एकेडेमिया, स्टार्टअप और इंडस्ट्री मिलकर कटिंग-एज सॉल्यूशन बनाते हैं। लगभग 6,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च और डेवलपमेंट सेल की स्थापना से बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूशन में जिज्ञासा और पूछताछ का एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर बढ़ता है। ₹50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) का बनना, भारत के साइंस और इनोवेशन के माहौल में एक अहम पल है। अलग-अलग फील्ड में लेटेस्ट रिसर्च को फंड और कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया गया NRF, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और सरकार के बीच सहयोग को और गहरा करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप के लिए ज़रूरी हाई-रिस्क, हाई-इम्पैक्ट रिसर्च को सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर, ये सुधार एक ऐसा एजुकेशन और इनोवेशन सुपरस्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक अहम पॉलिसी को दिखाते हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाला, भविष्य के लिए तैयार और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव हो, और एक आत्मनिर्भर और ज्ञान पर चलने वाले भारत के लिए इंटेलेक्चुअल नींव रखे।

#### **4.2 एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच ब्रिजिंग: YUGM मॉडल:**

टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन और ग्लोबल नॉलेज कॉम्पिटिशन वाले इस दौर में, भारत सरकार ने YUGM पेश किया है—यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी मॉडल है जो एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकार के बीच 'कॉन्फ्लिक्ट' के प्रिंसिपल को दिखाता है। YUGM को हाई-इम्पैक्ट रिसर्च को कैटलाइज़ करने, नेक्स्ट-जेनरेशन इनोवेटर्स को नर्चर करने और ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइज़ेशन को फास्ट-ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। असल में, YUGM भारत सरकार और वाधवानी फाउंडेशन के बीच ₹1,400 करोड़ का कोलेबोरेटिव इन्वेस्टमेंट है, जो नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के एक बोल्ट नए पैराडाइम को दिखाता है। यह मॉडल कटिंग-एज साइंस के लिए गहरे इंस्टीट्यूशनल लिंकेज और स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाकर भारत की रिसर्च-टू-मार्केट पाइपलाइन में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करता है।

#### **4.3 वाधवानी स्कूल ऑफ़ AI एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स – IIT कानपुर:**

₹500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट सेंटर 150,000 sq. ft. में फैला होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के लिए एक फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। B.Tech से लेकर पोस्टडॉक्टरल रिसर्च तक डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हुए, यह स्कूल साइबर सिक््योरिटी, रोबोटिक्स, AI गवर्नेंस और एथिक्स, और एप्लाइड मशीन लर्निंग जैसे फ्रंटियर एरिया में इंटरडिसिप्लिनरी R&D को एंकर करेगा। यह फैसिलिटी पूरे भारत में 50 एक्सटर्नल इनोवेशन हब भी बनाएगी, जो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, डिज़ास्टर

मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ जैसे सेक्टर में AI-ड्रिवन सॉल्यूशन लाएगी। स्कूल का मकसद भारत के सोशियो-इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट के हिसाब से स्वदेशी AI कैपेसिटी को बढ़ावा देते हुए एक ग्लोबल टैलेंट मैग्रेट बनना है।

#### **4.4 वाधवानी हब फॉर बायोसाइंसेज एंड हेल्थ – IIT बॉम्बे:**

₹300 करोड़ के एलोकेशन के साथ, यह 120,000 sq. ft. फैसिलिटी मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिस्टम इनोवेशन और बायोटेक रिसर्च पर फोकस करेगी। यह हब सस्ते मेडिकल डिवाइस, डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के डिजाइन और डिप्लॉयमेंट में मदद करेगा। यह एक ट्रांसलेशनल रिसर्च एक्सेलेरेटर के तौर पर काम करेगा, जो बड़े पैमाने पर समाज पर असर डालने के लिए एकेडमिक खोजों को क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल रास्तों से जोड़ेगा।

#### **4.5 ANRF के साथ नेशनल को-फंडिंग फ्रेमवर्क:**

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के तहत ₹200 करोड़ का एक अलग कॉर्पस, लेट-स्टेज रिसर्च की को-फंडिंग को मुमकिन बनाएगा, जिससे इंटेलेक्चुअल कैपिटल को कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ में बदला जा सकेगा। टारगेट एरिया में AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेज, स्मार्ट मोबिलिटी, एडवांस्ड मटीरियल्स और सस्टेनेबल एनर्जी शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टिज़ और रिस्क कैपिटल का फ़ायदा उठाकर, यह फ्रेमवर्क अच्छी टेक्नोलॉजी को लैब से इकॉनमी में बदलने में मदद करता है। साथ में, ये इंटरवेंशन अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं ज़्यादा दिखाते हैं। YUGM सिर्फ़ अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स की एक सीरीज़ नहीं है—यह भारत के इनोवेशन प्र्यूचर के लिए एक स्केलेबल पॉलिसी ब्लूप्रिंट है, जो मिशन-ड्रिवन, क्रॉस-सेक्टरल कोलेबोरेशन के लिए एक रेप्लिकेबल मॉडल देता है। यह एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच पारंपरिक रुकावटों को दूर करता है, रिसर्च को रियल-वर्ल्ड आउटकम में बदलता है और यह पक्का करता है कि भारतीय इनोवेशन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव हो।

#### **4.6 AI और भविष्य की टेक, स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों के तौर पर:**

भारत खुद को सिर्फ़ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर के तौर पर ही नहीं, बल्कि इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक टेक लीडरशिप के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पर भी बना रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में स्पीड, स्केल और सॉवरेनिटी पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने एक साफ़ आदेश दिया: आइडिया से प्रोटोटाइप और फिर प्रोडक्ट तक के सफ़र को इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल कन्वर्जेंस के ज़रिए तेज़ किया जाना चाहिए। इस विज़न के दिल में “Make AI in India और Make AI Work for India” का नेशनल कमिटमेंट है। यह डुअल-पर्पस फ्रेमवर्क इंडिया-AI मिशन के ज़रिए चलाया जा रहा है, जो एक पॉलिसी इनिशिएटिव है जो सभी बड़े इंस्टीट्यूशन में AI सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस को जोड़ता है, जिन्हें बेसिक रिसर्च, स्वदेशी एल्गोरिदम और सेक्टर-स्पेसिफिक AI एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। IIT और AIIMS के बीच कोलेबोरेशन के ज़रिए मेडिकल एजुकेशन में AI को शामिल करने के लिए एक ठोस कोशिश, मेडिटेक, डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ डेटा साइंसेज में प्रैक्टिशनर्स और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी तैयार करना।

#### **4.6 बराबर नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना:**

भारत की AI और भविष्य की टेक स्ट्रेटेजी, ग्लोबल नॉलेज सिस्टम तक पहुंच को डेमोक्रेटाइज़ करने के बड़े कमिटमेंट पर टिकी है। वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन पहल के लॉन्च से देश भर में इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स तक पहुंच मिलती है, जिससे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्टार्ट-अप्स, चाहे उनकी जगह या इनकम कुछ भी हो, ग्लोबल साइंटिफिक लिटरेचर में सबसे आगे रह सकते हैं। यह सिर्फ़ एक डिजिटल इनक्लूजन पॉलिसी नहीं है—यह एकेडमिक इक्विटी और इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक स्ट्रक्चरल इनेबलर है।

#### 4.7 इनोवेशन इकोनॉमी के लिए स्किलिंग:

यह मानते हुए कि भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भविष्य के लिए तैयार टैलेंट की ज़रूरत है, सरकार ने PM विद्या लक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जो एजुकेशन फाइनेंसिंग को स्किलिंग पाथवे के साथ जोड़ती है, जिससे आसानी से लोन, स्कॉलरशिप और करियर गाइडेंस मिलती है। साथ ही, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में 7,000 से ज़्यादा इंटरशिप और इनोवेशन सेल बनाए गए हैं, जो करिकुलम और इंडस्ट्री के बीच ब्रिज का काम करते हैं। ये सेल R&D लैब, स्टार्ट-अप और ग्लोबल कॉर्पोरेशन के लिए रियल-टाइम एक्सपोज़र देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स AI, क्रांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और नई टेक में इंडस्ट्री से जुड़ी काबिलियत डेवलप कर सकते हैं। पॉलिसी, पढ़ाने के तरीके और प्रैक्टिस को मिलाकर बने इस इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के ज़रिए, भारत न सिर्फ़ टेक्नोलॉजिकल काबिलियत बना रहा है, बल्कि एक मज़बूत, सबको साथ लेकर चलने वाली और भविष्य को ध्यान में रखकर चलने वाली इनोवेशन इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है। AI और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी अब सिर्फ़ सेक्टर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं—वे स्ट्रेटेजिक ज़रूरतें हैं जो आने वाले दशकों में भारत की राह तय करेंगी।

#### 4.8 ग्लोबल पहचान और स्ट्रेटेजिक आउटरीच:

ग्लोबल एकेडमिक स्टेज पर भारत की बढ़त सिर्फ़ घरेलू सुधार की कहानी नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक आउटरीच और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन की भी कहानी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश का बढ़ना—2014 में 9 इंस्टीट्यूशन से 2025 में 46 तक—अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी में एक दशक के सोचे-समझे इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। यह उछाल भारत के नॉलेज कंज्यूमर से दुनिया भर में सम्मानित नॉलेज प्रोड्यूसर बनने के बदलाव को दिखाता है। अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस और दुबई में IIM अहमदाबाद का कैंपस बनना भारत की एजुकेशन डिप्लोमेसी में एक अहम कदम है। ये विदेशी इंस्टीट्यूशन भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल के एंबेसडर के तौर पर काम करते हैं, भारत के एजुकेशनल फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं और क्रॉस-बॉर्डर एकेडमिक नेटवर्क को बढ़ावा देते हैं। साथ ही, पॉलिसी रिफॉर्म जो विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की इजाज़त देते हैं, वे दो-तरफ़ा एकेडमिक एक्सचेंज के लिए कमिटमेंट का संकेत देते हैं, जो न सिर्फ़ अंदरूनी इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं बल्कि बाहरी जुड़ाव को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत का रिसर्च इकोसिस्टम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ बेहतर होता है। इंडियन एजुकेशनल एक्सीलेंस को एक्सपोर्ट करते हुए ग्लोबल एकेडमिक डाइवर्सिटी को इंपोर्ट करने की यह डुअल-ट्रैक स्ट्रेटेजी एक कॉन्फिडेंट, आगे की सोच वाले भारत को दिखाती है—जो ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी को सिर्फ़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बल्कि उसे आकार दे रहा है।

#### 4.9 विकसित भारत@2047 की ओर:

YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव सिर्फ़ एक इवेंट नहीं था—यह पॉलिसी में एक अहम पल था। इसने मोदी सरकार के कई दशकों के विज़न को पक्का किया, जिसके तहत 2047 तक भारत को विकसित भारत में बदलना है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता को युवाओं के एम्पावरमेंट के साथ, एजुकेशन रिफॉर्म को ग्लोबल आउटरीच के साथ, और इनोवेशन इकोसिस्टम को इनक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ अलाइन किया गया है। रिसर्च फंडिंग, जिसमें ₹50,000 करोड़ का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी शामिल है, को लैब से मार्केट तक इनोवेशन को एनर्जी देने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडस्ट्री-एकेडमिया पार्टनरशिप, जैसे कि YUGM मॉडल के तहत, को-क्रिएशन और प्रॉब्लम-सॉल्विंग के कल्चर को इंस्टीट्यूशनल बना रही हैं। युवाशक्ति, यानी भारत के युवा, इस बदलाव के पैसिव बेनिफिशियरी नहीं हैं, बल्कि एक्टिव आर्किटेक्ट हैं—जो AI, बायोटेक, क्रांटम और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में लीड करने के लिए स्किल्स, टूल्स और प्लेटफॉर्म से लैस हैं। असल में, भारत की इनोवेशन जर्नी अब पॉलिसी-बैकड, ग्लोबली एंगेज्ड और फ्यूचर-फेसिंग है।

जैसे-जैसे देश 2047 में अपनी आज़ादी की सौवीं सालगिरह की ओर बढ़ रहा है, वह भारतीय मूल्यों और ग्लोबल विज्ञान पर आधारित एक सेल्फ-रिलायंट, इनोवेशन-ड्रिवन इकॉनमी बनने के साफ़ लक्ष्य के साथ ऐसा कर रहा है। YUGM कॉन्क्लेव ने फिर से कन्फर्म किया कि यह भविष्य इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा-इसे भारत में, भारत द्वारा और दुनिया के लिए बनाया जाएगा।

## 5. इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप:

इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप वे डायनामिक ताकतें हैं जो मॉडर्न बिज़नेस की दुनिया को पावर देती हैं। इनोवेशन तरक्की के लिए कैटलिस्ट है, जो नए आइडिया में जान डालता है और मौजूदा प्रोसेस को बेहतर बनाता है। बदले में, एंटरप्रेन्योरशिप वह ज़रिया है जो इन इनोवेशन को फलते-फूलते बिज़नेस में बदलता है। यह डायनामिक इंटरप्ले बिज़नेस की दुनिया में सफलता की नींव है। इनोवेशन शुरुआती आइडिया को जगाता है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप उसे पूरा करने में मदद करती है। साथ मिलकर, वे न केवल अलग-अलग बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। इस आर्टिकल में, हम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच के मुश्किल तालमेल को देखेंगे, और बताएंगे कि वे बिज़नेस के भविष्य को बनाने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और इस तालमेल को समझते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, वे अपने वेंचर में चुनौतियों का सामना करने और मौकों का फ़ायदा उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे।

## 5.1 इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को समझना

**5.1.1 इनोवेशन:** इनोवेशन बिज़नेस की दुनिया में तरक्की के पीछे की ड्राइविंग फ़ोर्स है। इसमें कुछ नया पेश करने या मौजूदा प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस को बेहतर बनाने का प्रोसेस शामिल है। यह कई तरह से हो सकता है, टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव से लेकर छोटे लेकिन असरदार सुधार तक। जो कंपनियाँ इनोवेशन को प्राथमिकता देती हैं, उनके आगे रहने, बदलती मार्केट की माँगों के हिसाब से ढलने और अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करने की संभावना ज़्यादा होती है।

(i) Airbnb का शेयरिंग इकॉनमी मॉडल: Airbnb ने ट्रैवल और रहने की जगह की इंडस्ट्री को बदल दिया, जिससे लोगों को अपने घर या खाली कमरे यात्रियों को किराए पर देने की सुविधा मिली, जिससे डेस्टिनेशन का अनुभव करने का एक नया तरीका बना।

(ii)

CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी: इस क्रांतिकारी जीन-एडिटिंग टूल में जेनेटिक बीमारियों का इलाज करने, बीमारी से बचाने वाली फसलें बनाने और कुछ बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता है।

**5.1.2 एंटरप्रेन्योरशिप:** एंटरप्रेन्योरशिप वह पुल है जो नए आइडिया को असल, कामयाब बिज़नेस में बदलता है। इसमें मार्केट में मौकों को पहचानना, रिसोर्स जुटाना और किसी विज्ञान को असलियत में बदलने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना शामिल है। एंटरप्रेन्योर पायनियर होते हैं, जो सोच-समझकर रिस्क लेने और बिज़नेस ओनरशिप की मुश्किलों से निपटने को तैयार रहते हैं। वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और अपनी इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

1. ओपरा विनफ्रे: एक आम बैकग्राउंड से, विनफ्रे ने अपने टेलीविज़न नेटवर्क, मैगज़ीन और प्रोडक्शन कंपनी के ज़रिए अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाते हुए एक मीडिया एम्पायर बनाया।
2. एलन मस्क: PayPal, SpaceX और Tesla को-फाउंड करने के लिए जाने जाने वाले मस्क एक विज्ञानरी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है।

## 5.2 इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ड्राइवर

- टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: डिजिटल इकॉनमी की ओर बदलाव इनोवेशन का एक बड़ा ड्राइवर है, खासकर उभरते मार्केट में।
- मार्केट की ज़रूरतें और ट्रेंड्स: कस्टमर की बदलती ज़रूरतें एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए सॉल्यूशन देने के मौके बनाती हैं।
- रिसोर्स मैनेजमेंट: सफल वेंचर्स के लिए ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स, दोनों का असरदार मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।

## 5.3 मॉडर्न इकॉनमी में भूमिका

- सस्टेनेबिलिटी: इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉम्बिनेशन लंबे समय तक बिज़नेस के बने रहने और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है।
- इकोनॉमिक असर: ये एलिमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाने, उसे बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि ET टेलीकॉम ने बताया है।
- एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी: इसमें सिर्फ नए आइडिया डूढ़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें लागू करना भी शामिल है, ruduct.com की यह PDF देखें।

## 6. भारत में स्किल डेवलपमेंट:

आज़ादी के बाद, भारत की एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया, जिससे वोकेशनल ट्रेनिंग को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज़ कर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) और उसके बाद की पहलों जैसे नेशनल स्किल्स पॉलिसी (2009) और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन (NSP 2015) के साथ ही वोकेशनल एजुकेशन पर पॉलिसी में ध्यान दिया जाने लगा। NSP 2015 का टारगेट 2022 तक 400 मिलियन लोगों को ट्रेन करना था, जिसका ज़िक्र अब हाल के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। उस लक्ष्य को पाने के तरीके ये थे: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) (2015 से अब तक), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) (2014 से अब तक), और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) (2016 से अब तक) जिनसे स्किल की बड़ी कमी को दूर करने का वादा किया गया था। फिर भी, बड़े लक्ष्यों और बड़े सरकारी निवेश के बावजूद, पिछले एक दशक में भारत का स्किल डेवलपमेंट का माहौल सिर्फ़ क्वांटिटी पर आधारित मेट्रिक्स और शक वाली सफलता की कहानियों में फंसा रहा है।

### 6.1 वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेंड्स का डेटा:

हालांकि फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग में मामूली बढ़ोतरी हुई है और यह 4.1% हो गई है, लेकिन इनफॉर्मल ट्रेनिंग के तरीके—खासकर खानदानी (2017 में 1.45 से 2023 में 11.6%) और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (2017 में 2.04% से 2023 में 9.3%)—बढ़े हैं। पिछले 3 सालों में किसी भी तरह की ट्रेनिंग न लेने वाले लोगों की संख्या में इतनी तेज़ी से कमी आना यह सवाल उठाता है कि डेटा की रिकॉर्डिंग में कैसे बदलाव आया होगा।

**टेबल 1: 15-59 साल के बीच के वोकेशनल ट्रेनिंग पाने वाले लोगों का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन**

| साल                        | 2004-05 | 2011-12 | 2017-18 | 2022-23 | 2023-24 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| फॉर्मल ट्रेनिंग            | 2.4%    | 2.4%    | 1.8%    | 3.8%    | 4.1%    |
| नॉन-फॉर्मल (हेरेडिटरी)     | 4.4%    | 1.8%    | 1.45%   | 7.9%    | 11.6%   |
| नॉन-फॉर्मल (सेल्फ-लर्निंग) | 3.9%    | 1.1%    | 1.67%   | 5.7%    | 7.1%    |

|                       |       |       |        |       |       |
|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| नॉन-फॉर्मल (ऑन द जॉब) | –     | 1.7%  | 2.04%  | 7.7%  | 9.3%  |
| कोई ट्रेनिंग नहीं     | 87.8% | 92.6% | 92.59% | 72.6% | 65.3% |

सोर्स: NSSO EUS और PLFS सर्वे (अलग-अलग साल)

रहस्य यह है कि वर्क फ़ोर्स (WF) में पहले से मौजूद ऐसे वर्कर्स की संख्या में अचानक बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिन्हें एक दिन से एक हफ़्ते तक का रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL) दिया गया है, जो खुद से सीखे/जॉब स्किल्स वाले लोगों को सर्टिफ़ाई करने का एक तरीका है। RPL ट्रेड लोगों की बड़ी संख्या, जो कई बार 24 घंटे से कम समय के कोर्स करते हैं, इस अचानक फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से ट्रेड लोगों की संख्या में बढ़ोतरी का एक सही कारण हो सकता है। सरकारी डेटा शॉर्ट-टर्म कोर्स पर चिंताजनक निर्भरता को उजागर करता है। PMKVY, जन शिक्षण संस्थान (JSS), और दूसरी स्कीमें मुख्य रूप से छोटी ट्रेनिंग देती हैं - कभी-कभी 10 दिन जितनी छोटी। 2017-18 में, 29% वोकेशनल ट्रेनी ने दो साल से ज़्यादा समय तक चलने वाले कोर्स किए, जो छह साल में आधे हो गए। 2023-24 तक, यह आँकड़ा गिरकर सिर्फ़ 14.29% रह गया। इस बीच, छह महीने से कम समय के कोर्स में शामिल होने वाले ट्रेनी का हिस्सा 22% से बढ़कर 44% हो गया। यह बदलाव दिखाता है कि सिस्टम में अच्छे स्किल डेवलपमेंट के बजाय जल्दी सर्टिफ़िकेशन को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।

**टेबल 2: शॉर्ट-टर्म कोर्स पर चिंताजनक निर्भरता**

| स्कीम                                   | ट्रेन किए गए लोगों की संख्या |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| PMKVY (2015-2023)                       | 140.81 लाख                   |
| जन शिक्षण संस्थान (2018-2023)           | 2.96 लाख                     |
| क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (2018-2023) | 5.11 लाख                     |

सोर्स: राज्यसभा सवाल (2024)

### 6.2 फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम और असल इंडस्ट्री की मांगों के बीच अंतर:

यह अंतर फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम और असल इंडस्ट्री की मांगों के बीच अंतर को दिखाता है। युवाओं में बेरोज़गारी की दर 17.5% के अब तक के सबसे ऊंचे लेवल से कम हुई है, लेकिन अभी भी डबल डिजिट में है, जो आम और वोकेशनल ट्रेनिंग की बढ़ती संख्या के साथ अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। इससे फिर से इन कोर्स की क्वालिटी पर सवाल उठता है, जो लोगों को नौकरी लायक स्किल नहीं दे रहे हैं।

**टेबल 3: युवा बेरोज़गारी के ट्रेड के आंकड़े इस संकट में एक और परत जोड़ते हैं**

| साल   | 2004-05 | 2011-12 | 2017-18 | 2022-23 | 2023-24 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| पुरुष | 6.2%    | 6.0%    | 17.3%   | 9.7%    | 9.8%    |
| महिला | 4.4%    | 6.8%    | 17.9%   | 10.6%   | 11.0%   |
| कुल   | 5.7%    | 6.2%    | 17.5%   | 10.0%   | 10.2%   |

फॉर्मली वोकेशनली ट्रेड लोगों के लिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट 2004-05 में 12 लाख से बढ़कर 2023-24 में 19.8 लाख हो गई, जबकि इनफॉर्मली ट्रेड लोगों के लिए यह 3.1 लाख से बढ़कर 7.6 लाख हो गई। ये नंबर भारत के स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम में गहरी स्ट्रक्चरल कमियों को दिखाते हैं। भारत का वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम एक नंबर

गेम बन गया है, जहाँ बिना किसी मतलब की स्किल सीखे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग पर बढ़ती निर्भरता, नौकरी के खराब नतीजे, और प्लेसमेंट के बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए आंकड़े सिस्टम की नाकामियों को दिखाते हैं। अगर भारत सच में एक ग्लोबल स्किल हब बनना चाहता है, तो उसे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को प्राथमिकता देनी होगी, लॉन्ग-टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना होगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग में प्राइवेट सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी, न कि उन्हें सिर्फ दर्शक बने रहना होगा। इससे कम कुछ भी बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे लाखों युवा भारतीयों के साथ नाइंसाफी होगी।

## 7. निष्कर्ष

स्किल डेवलपमेंट कोर्स का समय तेज़ी से कम हो रहा है। इसलिए, कुल मिलाकर, ज़्यादा लोग डिग्री/सर्टिफिकेट या फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इन कोर्स का समय बहुत कम है – कुछ मामलों में, सिर्फ 10 दिन। इन शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (STT) कोर्स में बढ़ोतरी के साथ यह भी है कि 2011-12 में भारत में 96.4% लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन में 15 साल से कम समय बिताया, और यह संख्या अब 2022-23 (NSSO, अलग-अलग राउंड) में घटकर 95.8% हो गई है, जबकि इसी समय में फॉर्मल एजुकेशन लेने वालों की हिस्सेदारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हर साल, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय चार से पांच हज़ार करोड़ रुपये खर्च करता है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद कितने कैंडिडेट को नौकरी मिली, यह बताने वाला शायद ही कोई पब्लिकेशन मौजूद हो। स्किल इंडिया मिशन की नींव होने के बावजूद, PMKVY को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा निर्भरता और प्लेसमेंट रेट में ठहराव शामिल है। इन कोर्स के प्लेसमेंट के आंकड़े बहुत शक वाले हैं, जहाँ PMKVY ने 54% प्लेसमेंट की रिपोर्ट दी थी, लेकिन डेटा से पता चलता है कि सिर्फ 22.16% प्लेसमेंट हुआ। ये कोर्स, जो 24 घंटे या 3 दिन जितने कम समय के होते हैं, आम तौर पर प्राइवेट, NSDC से फंडेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर देते हैं। PMKVY 1.0 (2015 में लॉन्च) के लिए प्लेसमेंट रेट 18.4% था, जो PMKVY 2.0 के तहत थोड़ा बढ़कर 23.4% हो गया, और फिर PMKVY 3.0 के तहत तेज़ी से घटकर 10.1% हो गया। फिर भी, इस स्कीम को अच्छी-खासी फंडिंग मिल रही है, और PMKVY 4.0 2024 में शुरू होगा, जिसे 12,000 करोड़ रुपये के बजट एलोकेशन से सपोर्ट मिलेगा (PMKVY, 2024)।

## 8. संदर्भ

1. एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लेबर फ़ोर्स, वॉल्यूम-3. नई दिल्ली: लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. भारत सरकार (2015).
2. एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लेबर फ़ोर्स. नई दिल्ली: लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. भारत सरकार (2022b). विज़न इंडिया@2047- गवर्नेंस. अभिनव पहल. <https://abhinavpahal.nic.in/pdf/vision%202047.pdf>
3. एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लेबर फ़ोर्स, वॉल्यूम-3. नई दिल्ली: लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. भारत सरकार (2015).
4. एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लेबर फ़ोर्स. नई दिल्ली: लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. भारत सरकार (2022b). विज़न इंडिया@2047- गवर्नेंस. अभिनव पहल. <https://abhinavpahal.nic.in/pdf/vision%202047.pdf>
5. भारत सरकार (2011). रोज़गार पर लोगों को दूसरी सालाना रिपोर्ट। नई दिल्ली: श्रम और रोज़गार मंत्रालय। भारत सरकार (2013-14)।

6. भारत सरकार (2011). रोज़गार पर लोगों को दूसरी सालाना रिपोर्ट। नई दिल्ली: श्रम और रोज़गार मंत्रालय। भारत सरकार (2013-14)।
7. <https://economictimes.indiatimes.com/opinion/et-commentary/reinventing-education/articleshow/5345874>.
8. सैनी, वंदना. "भारत में स्किल डेवलपमेंट: ज़रूरत, चुनौतियाँ और आगे के रास्ते।" अभिनव नेशनल मंथली रेफरीड जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन आर्ट्स एंड एजुकेशन 4.4 (2015)।
9. शर्मा, लवीना, और आशा नागेंद्र. "भारत में स्किल डेवलपमेंट: चुनौतियाँ और मौके।" इंडियन जर्नल ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 9.48 (2016)।